†श्री तंगामणि : केन्द्रीय सरकार । यह केवल पंजाब सरकार का ही मामला नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि अनुपात में कुछ कमी या अधिकता है तो यह उनका काम है कि उसे ठीक करें । शुल्क लगाने उसे वसूल करने तथा राज्य में शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : यह पंजाब सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच विवाद का प्रश्न है ।

†अध्यक्ष महोदय : इस मामले में पंजाब सरकार व केन्द्रीय सरकार में अगर कोई मतभेद है भी तो भी उसका फैसला लोग कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं कर सकते ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : राज्य विधान मंडल के सत्र के अन्तिम दिन एक अध्यादेश निकाला गया था ।

†अध्यक्ष महोदय : संविधान के अधीन अध्यादेश निकाला जा सकता है ।

मैं इन प्रस्तावों को अस्वीकृत करता हूँ ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वहां शान्ति भंग हो गई है ; औरतों को पीटा गया है और लोगों की मृत्यु हो चुकी है ।

†अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । वहां भी तो राज्य सरकार है ।

†श्री तंगामणि : गृह-कार्य मंत्री के उत्तर के बाद आप ने मुझे अवसर देने की बात कही थी । मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे चुका हूँ । इस विषय पर हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है । मैंने प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया है ।

†श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : यह मामला केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच का है । अच्छी प्रकार से चर्चा हुये बिना ही शुल्क लगा दिया गया है । अतः निवदन है कि आप हमारी बातें सुनें ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री ।

अमरीका और टर्की, ईरान और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता के लिए हुए करार के बारे में वक्तव्य

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जैसा कि मैं ने कल वादा किया था, वक्तव्य मेरे पास तैयार है, मैं उसे सभा पटल पर रखूंगा । मैं उसे पढ़ कर सुनाऊं या सभा पटल पर रखूं, आप की क्या इच्छा है ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या लम्बा वक्तव्य है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : उसे पढ़ने में १० या ११ मिनट लगेंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह वक्तव्य महत्वपूर्ण विषय के संबंध में है अतः यदि उसे सभा में पढ़ कर सुनाया जा सके तो सुनाया जाय ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि आपकी इच्छा है तो मैं उसे पढ़ कर सुनाऊंगा ।

यह वक्तव्य अभी हाल में अमरीका और टर्की, ईरान और पाकिस्तान के बीच हुये सैनिक सहायता के तीन करारों के संबंध में है ।

२६ जुलाई, १९५८ को बगदाद करार परिषद की एक बैठक लंदन में हुई थी । यह बैठक इराक की क्रान्ति के तुरन्त बाद हुई थी । इस बैठक में ईरान, पाकिस्तान, टर्की और ब्रिटेन के प्रधान मंत्रियों तथा अमरीका के विदेश मंत्री श्री डलेस की ओर से एक घोषणा जारी की गयी थी । घोषणा की एक प्रति इस वक्तव्य के साथ संलग्न है । घोषणा के अन्तिम पैरे में अमरीका की ओर से दिये गये वचन का उल्लेख है । यह पैरा इस प्रकार है :

“ २४ फरवरी, १९५५ को बगदाद में आपसी सहयोग के सम्बन्ध में जिस करार पर हस्ताक्षर किये गये थे, उसके अनुच्छेद १ में यह व्यवस्था की गई है कि समझौते में सम्मिलित सभी पक्ष अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए सहयोग करेंगे और इस प्रकार के सहयोग को क्रियात्मक रूप देने के उद्देश्य से वे जिन उपायों को करने के लिये सहमत हों, उनके लिए अलग समझौते किये जा सकते हैं । इसी प्रकार अमरीका भी विश्व शांति के हित में और कांग्रेस द्वारा दिये गये वर्तमान अधिकारों के अनुसार इस घोषणा में सम्मिलित देशों को उनकी सुरक्षा और बचाव के लिए सहयोग देना स्वीकार करता है और इस प्रकार के सहयोग को क्रियात्मक रूप देने के लिए वह समझौते करने के लिए तत्पर रहेगा । ”

अमरीका की ओर से दिये गये इस वचन के अनुसार मार्च, १९५६ के आरम्भ में अंकारा में बातचीत शुरू हुई और ५ मार्च को अमरीका ने टर्की, ईरान और पाकिस्तान के साथ अलग अलग तीन करार किये । ये तीनों करार बिल्कुल एक ही तरह के हैं । पाकिस्तान और अमरीका के साथ हुये करार की एक प्रति इस वक्तव्य के साथ संलग्न है ।

५ मार्च, १९५८ के इस करार का अनुच्छेद १ इस प्रकार है :—

“ पाकिस्तान की सरकार आक्रमण का सामना करने के लिए कटिबद्ध है । यदि पाकिस्तान पर आक्रमण किया गया तो वहां की सरकार के अनुरोध पर उसकी सहायता के लिए अमरीका की सरकार अपने राष्ट्र के संविधान के अनुसार ऐसी कार्यवाही करेगी, जिसमें सेनाओं का प्रयोग भी सम्मिलित है, जो दोनों देशों में आपस में तय होगी, और जो मध्य-पूर्व में शांति और व्यवस्था कायम रखने सम्बन्धी संयुक्त संकल्प के अनुसार होगी । ”

इस अनुच्छेद से यह स्पष्ट है कि अमरीका ने, पाकिस्तान पर आक्रमण होने पर, वहां की सरकार के अनुरोध पर उसकी सहायता करना स्वीकार किया है और इसके लिए वह सभी उचित उपाय करेगा, जिसमें सेनाओं का प्रयोग भी सम्मिलित है । परन्तु ये उपाय :—

(अ) अमरीका के संविधान के अनुसार होने चाहियें; और

(ब) मध्य-पूर्व में शांति और स्थिरता स्थापित रखने के सम्बन्ध में स्वीकार किये गये संयुक्त संकल्प के, जिसे साधारणतया "आइजनहावर सिद्धान्त" कहा जाता है, अनुसार होंगे ।

अमरीका के संविधान के अनुसार वहाँ की कांग्रेस की विशेष आज्ञा के बिना अमरीकी सेनाएं किसी दूसरे देश की सहायता के लिए नहीं भेजी जा सकतीं । पारस्परिक सुरक्षा अधिनियम के अनुसार अमरीकी सरकार को अन्य देशों को आर्थिक और सैनिक सहायता देने का अधिकार है, परन्तु अमरीकी सेनाएं किसी दूसरे देश के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकतीं । परन्तु अमरीकी कांग्रेस के ६ मार्च, १९५७ के संयुक्त संकल्प के अनुसार कांग्रेस की खास आज्ञा के बिना भी वहाँ की सेनायें दूसरे देश की सहायता के लिए प्रयोग की जा सकती हैं । इस संयुक्त संकल्प की, जिसे साधारणतया मध्य-पूर्व के लिए आइजनहावर सिद्धान्त कहा जाता है, एक प्रति वक्तव्य के साथ संलग्न है ।

इस संयुक्त संकल्प की धारा २ में कहा गया है :—

"राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह मध्य-पूर्व के क्षेत्र में किसी भी ऐसे देश या देशों की सैनिक सहायता के कार्यक्रम को हाथ में ले सकें, जो सहायता प्राप्त करना चाहते हों । अमरीका की दृष्टि में विश्व में शान्ति बनाये रखने के लिए मध्य-पूर्व के देशों की स्वतंत्रता और अक्षुण्णता की रक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझें तो अमरीका किसी भी ऐसे देश के, या देशों की सहायता के लिए अपनी सेनाओं का प्रयोग करने को तैयार है, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद द्वारा नियंत्रित किसी देश के हमले के खिलाफ उससे सहायता का अनुरोध किया हो, लेकिन शर्त यह है कि अमरीकी सेनाओं का प्रयोग अमरीकी संविधान के अनुसार तथा अमरीका द्वारा की गई संधियों के दायित्व के अनुसार किया जायेगा ।"

वक्तव्य के साथ संलग्न दस्तावेजों और मुख्यतया उपरोक्त अंशों को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि अमरीकी सरकार पाकिस्तान को न केवल आर्थिक और सैनिक सहायता देना जारी रखेगी, बल्कि यदि पाकिस्तान पर कोई ऐसा देश आक्रमण करे, जो अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के नियंत्रण में हो तो पाकिस्तान की सरकार की सहायता के लिये उसके अनुरोध पर अमरीकी सेनाओं का प्रयोग भी करेगी ।

लेकिन पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने इस करार की व्यापक व्याख्या की है । पाकिस्तान द्वारा दी गयी व्याख्या तथा इस करार द्वारा उत्पन्न संदेहों को देखते हुए अमरीकी सरकार से स्पष्टीकरण के लिये कहा गया । अमरीका के अधिकारियों ने हमें विश्वास दिलाया है कि पाकिस्तान के साथ जो नया द्विपक्षीय करार किया गया है, उसका असर केवल यह है कि पाकिस्तान को आइजनहावर सिद्धान्त के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है और आइजनहावर सिद्धान्त के अनुसार अमरीकी सेनायें केवल तभी काम में लाई जा सकती हैं यदि पाकिस्तान पर कोई ऐसा देश हमला करे, जो अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के नियंत्रण में हो । इस के अतिरिक्त हमें यह आश्वासन खास तौर से दिया गया है कि नया करार भारत के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । अमरीकी अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस समझौते में कोई गुप्त धारारें नहीं हैं फिर और न कोई अलग पूरक युक्त समझौता है ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पाकिस्तान के प्रवक्ता समय-समय पर यह कहते रहे हैं कि अमरीका के साथ सुरक्षा सहायता सम्बन्धी करार करने का उनका उद्देश्य भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत करना ही है। हमने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान को दी गई अमरीकी सैनिक सहायता वहां के अधिकारियों में हमलावर प्रवृत्ति को उकसाती है और पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव और संघर्ष को बढ़ाती है। कुछ समय से हम यह देखते रहे हैं कि जम्मू और काश्मीर में तोड़-फोड़ और विनाश की कार्यवाइयों में पाकिस्तान ने अमरीका में बने हुए सैनिक सामान का प्रयोग किया है। यह कहना कठिन है कि यह सामान अमरीकी सैनिक सहायता के अनुसार पाकिस्तान को मिला है या उसने सामान्य व्यापारिक तौर पर वहां से खरीदा है। नये करार का पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने जो व्यापक अर्थ लगाया है, वह हमारे लिये बहुत चिन्ता का विषय बन गया है, खास तौर से इसलिये कि पिछले अनुभव से हमें यह स्पष्ट मालूम हुआ है कि पाकिस्तान की आक्रमक कार्यवाही बराबर बढ़ती ही गयी है।

अमरीका के प्राधिकारियों ने हमें जो आश्वासन दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं पर आक्रमण की परिभाषा करना वास्तव में कठिन है। पाकिस्तानी अधिकारी आक्रमण करते रहे हैं और फिर उस से इनकार भी करते रहे हैं। पिछले अनुभवों को देखते हुए और पाकिस्तान की लगातार धमकियों और नये करार की उसकी व्याख्या के कारण भारत के लिये यह विश्वास करना कठिन है कि दूसरे देशों से प्राप्त सहायता का वह भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं करेगा, यद्यपि दूसरे देशों ने हमें इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन दे दिया है। इसलिये हमने अमरीका से फिर अनुरोध किया है कि वह स्थिति को और भी अधिक स्पष्ट करे।

हम ने बार-बार यह दोहराया है कि हमारी यह निश्चित नीति है कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध या किसी और देश के विरुद्ध आत्मरक्षा के सिवाय और किसी भी दशा में सैनिक कार्यवाही नहीं करेंगे। हमें विश्वास है कि अमरीका की सरकार और वहां के लोग भारत के प्रति सद्भावना रखते हैं और वे किसी भी ऐसी व्यवस्था, चाहे वह औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक या खुली हो अथवा गुप्त, में शामिल नहीं होंगे, जिस से भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचता हो।

कल की चर्चा में एक और बात उठाई गई थी। हमारे एक वरिष्ठ पदाधिकारी मेजर जनरल हेण्डरसन ब्रक्स का जिक्र विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने किया। कहा गया कि वह भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं। इस पर मैंने कहा था कि मेजर जनरल ब्रक्स एक भारतीय राष्ट्रजन हैं और एक योग्य सक्षम तथा निष्ठावान पदाधिकारी हैं। श्री पटनायक ने मेरे इस कथन पर संदेह प्रकट किया था। मैंने मामले की जांच कराली है और स्थिति यह है।

मेजर जनरल ब्रक्स का जन्म बर्मा में हुआ था और १९२९ में उन्हें सम्राट के कमीशन प्राप्त भारतीय पदाधिकारी के रूप में कमीशन दिया गया। सम्राट के कमीशन प्राप्त सभी भारतीय पदाधिकारी भारतीय अधिवर्ती होते थे और मेजर जनरल ब्रक्स को सर्वदा भारतीय राष्ट्रजन माना गया है। १९५० में जब संविधान बना उस के शीघ्र बाद ही अन्य भारतीय सेना पदाधिकारियों की ही भांति उन्होंने भी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने विशेष योग्यता से कार्य सम्पन्न किया।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिंहट) : प्रधान मंत्री ने बताया कि यह द्विपक्षीय करार अमरीका के संविधान तथा उसके करार आभारों के संदर्भ में किया गया है। अतः मैं वैदेशिक कार्य मंत्रालय से निवेदन करूंगी कि वह हमें सीटो तथा अमरीका के परस्पर सुरक्षा अधिनियम की मूल प्रतियां उपलब्ध

कराये ताकि हम उन खण्डों का अध्ययन कर सकें। इस से हमें वैदेशिक कार्य मंत्रालय के वाद-विवाद में भी सहायता मिलेगी।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह उपलब्ध करा दी जा सकती है, वास्तव में कई बार इन्हें प्रकाशित किया जा चुका है। मैं समझता हूँ कि लोक सभा सचिवालय ने इन सब दस्तावेजों का एक संकलन प्रकाशित किया है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उस में उन करारों का ही संक्षिप्त विवरण है जिस में हम भी एक पक्ष हैं। उसमें उन करारों का उल्लेख नहीं है जिन में हम एक पक्ष नहीं हैं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्या हमें बतायें कि किन-किन दस्तावेजों की प्रतियां उन्हें चाहियें उन्हें वे सब मिल जायेंगी।

†अध्यक्ष महोदय : यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं एक प्रति मंगा दूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत के जीवन बीमा निगम का प्रतिवेदन

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २६ के अन्तर्गत भारत के जीवन बीमा निगम की १ सितम्बर, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक की अवधि के प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे सहित, सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० १२८२/५६]

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

†संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

- (१) अनुपूरक विवरण संख्या ३ छठा सत्र, १९५८
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १८]
- (२) अनुपूरक विवरण संख्या ७ पांचवां सत्र, १९५८
[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६]
- (३) अनुपूरक विवरण संख्या १६ चौथा सत्र, १९५८
[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०]
- (४) अनुपूरक विवरण संख्या १८ तीसरा सत्र, १९५७
[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१]
- (५) अनुपूरक विवरण संख्या २२ दूसरा सत्र, १९५७
[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२]
- (६) अनुपूरक विवरण संख्या २० पहला सत्र, १९५७
[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३]